



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072020-220596
CG-DL-E-20072020-220596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2020/आषाढ़ 29, 1942
No. 169]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2020/ASADHA 29, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

प्रकरण संख्या: सीवीडी-ओआई - 05/2020

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "60 डेनियर से अधिक के विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न" के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/26/2020-डीजीटीआर.— 1. एसोसिएशन ऑफ़ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया (एएमएफआईआई) (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तु की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "60 डेनियर से अधिक के विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से सस्मिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सस्मिडी प्राप्त संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन "60 डेनियर से अधिक के विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न" है। जिनमें (क) एम्ब्रायडरी अनुप्रयोगों के लिए बोविन पर प्रयोग के लिए तैयार यार्न/धागा तथा (ख) स्पूल स्पन प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादित यार्न शामिल नहीं हैं। इस उत्पाद को बाजार शब्दावली में विस्कोस फिलामेंट यार्न या रेयन फिलामेंट यार्न, आर्ट सिल्क यार्न, सेल्युलोज यार्न या रेयन यार्न के रूप में भी जाना जाता है। यह यार्न सिंगल या टिवस्टेड या डबल टिवस्टेड या अनटिवस्टेड हो सकता है। इसे तीन अलग-अलग प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं के जरिए उत्पादित किया जा सकता है – पोट स्पन यार्न (पीएसवाई), कंटीन्यूअस स्पन यार्न (सीएसवाई) और स्पून स्पन यार्न (एसएसवाई)। प्रत्येक प्रक्रिया के जरिए उत्पादित यार्न के विभिन्न विनिर्देशनों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रयोग होते हैं। वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पॉट स्पन यार्न और कंटीन्यूअस स्पन यार्न प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादित यार्न तक सीमित है।
4. यह उत्पाद अपने स्पर्श और टैक्सचर में रेशम, कपास और ऊन से मिलता जुलता है। इसका प्रयोग बुने हुए फैब्रिक, घर की सजावट, बुनाई और अन्य में होता है। यह जार्जेट, क्रैप्स और सिफॉन जैसे वस्त्रों को बनाने के लिए लोकप्रिय पसंद है।
5. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 54 के सीमाशुल्क शीर्ष 540120, 540331, 540332 और 540341 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद को 54012000, 54033100, 54033200, 54034110, 54034120, 54034130, 54034150, 54034170, 54034190, 54034290 और 54034990 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु से तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएमएफआईआई) द्वारा घरेलू उत्पादक मै. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों सहित दायर किया गया है। यह दावा किया गया है कि घरेलू उत्पादक मै. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित हैं।
8. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. कथित सस्मिडीकरण का आधार

9. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादक/ निर्यातक संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडियों से लाभान्वित हुए हैं जिनमें उन प्रदत्तों और जिलों की सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकाय शामिल हैं जहां ये उत्पादक/निर्यातक अवस्थित हैं। आवेदक ने संगत सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के संगत कानूनों, नियमों और विनियमों तथा अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है।
10. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित सस्मिडियों/कार्यक्रमों का आरोप लगाया गया है :

i. अनुदानों के रूप में अभिज्ञात स्कीम

कार्यक्रम संख्या 1: वस्त्र उद्योग के पुनर्गठन हेतु सहायता के लिए विशेष निधि और "वैश्विक बनने" के लिए चीन की वस्त्र कंपनियों के प्रयास।

कार्यक्रम संख्या 2: स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी निधि/विकास तथा विविधीकृत पुनर्उत्पादित सेल्यूलोज फाइबर की उच्च कार्यकुशलता, स्पिनिंग और स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन

कार्यक्रम संख्या 3: प्रौद्योगिकीय रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यम हेतु प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषन सहायता हेतु निधि।

कार्यक्रम संख्या 4: पारंपरिक उद्योग उन्नयन निधि – विज्ञान और प्रौद्योगिकी निधि हेतु प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 5: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध और व्यापार के विकास के लिए निवेश, व्यापार और आर्थिक सहयोग/निधि के विकास हेतु विशेष निधि।

कार्यक्रम संख्या 6: ऊर्जा, बचत प्रौद्योगिकी सुधार हेतु विशेष निधि/ ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के रूपांतरण हेतु प्रोत्साहन निधि।

कार्यक्रम संख्या 7: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान

कार्यक्रम संख्या 8: उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योगों हेतु अनुदान

कार्यक्रम संख्या 9: निस्तारण उपचार संयंत्र हेतु निधि

कार्यक्रम संख्या 10: हेनान प्रदेश के प्रादेशिक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त विभिन्न अनुदान

कार्यक्रम संख्या 11: जिलिन के प्रादेशिक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त विभिन्न अनुदान

कार्यक्रम संख्या 12: सिचुआन प्रदेश के प्रादेशिक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त विभिन्न अनुदान

II. टैक्स और वैट प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात स्कीम

कार्यक्रम संख्या 13: उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों हेतु अधिमानी कर नीतियां/ उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आयकर कटौती/ उद्यम कर कानून के अनुच्छेद-4 के अंतर्गत अनिवासी उद्यम (एन आर ई) के लिए अधिमानी आयकर

कार्यक्रम संख्या 14: पर्यावरण संरक्ष, ऊर्जा संरक्षण और अपेक्षाओं को पूरा करने वाली जल संरक्षण परियोजनाओं में कार्यरत उद्यमों हेतु कारपोरेट आयकर से छूट या कटौती।

कार्यक्रम संख्या 15: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्ययों की अतिरिक्त गणना और कटौती हेतु अधिमानी कर नीतियां/ अनुसंधान और विकास निवेशों हेतु अधिमानी आयकर लाभ

कार्यक्रम संख्या 16: स्वच्छ विकास तंत्र हेतु अधिमानी कर नीतियां

कार्यक्रम संख्या 17: उपकरण के आयात हेतु अधिमानी कर व्यवहार

कार्यक्रम संख्या 18: स्थिर परिसंपत्तियों पर त्वरित मूल्य ह्रास

कार्यक्रम संख्या 19: निर्यातों पर कर वापसी (निर्यात कर छूट)

कार्यक्रम संख्या 20: कम लाभ पर प्रचालित कंपनियों हेतु उपलब्ध कर अधिमान

कार्यक्रम संख्या 21: 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित उत्पादक एफआईई के लिए कम कर दर

कार्यक्रम संख्या 22: आयातित प्रौद्योगिकियों और उपकरण हेतु टैरिफ और आयात वैट से छूट

कार्यक्रम संख्या 23: संसाधनों के समेकित उपयोग पर अधिमानी वैट/ एफआईई के लिए वैट वापसी

III. ऋण और निर्यात वित्त पोषण के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम संख्या 24 अधिमानी ऋण प्रदान करना

कार्यक्रम संख्या 25 जीओसी द्वारा ऋण गारंटी/ क्रेडिट ऋण गारंटी/ निर्यात क्रेडिट गारंटियां

कार्यक्रम संख्या 26 एक्सपोर्ट- इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से अधिमानी निर्यात वित्त पोषण

कार्यक्रम संख्या 27 निर्यात विक्रेता ऋण

कार्यक्रम संख्या 28 निर्यात क्रेता ऋण

कार्यक्रम संख्या 29 निर्यात ऋण बीमा सब्सिडियां

IV. इक्विटी निवेश के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम संख्या 30 इक्विटी निवेश

कार्यक्रम संख्या 31 इक्विटी स्वेप्स के लिए ऋण

V. एल टी एआर के लिए वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम संख्या 32 पर्याप्त से कम मूल्य (एलटीएआर) पर कच्ची सामग्री

कार्यक्रम संख्या 33 पर्याप्त से कम मूल्य (एलटीएआर) पर प्रदत्त भूमि/भूमि उपयोग अधिकार

कार्यक्रम संख्या 34 पर्याप्त से कम मूल्य (एलटीएआर) पर प्रदत्त विद्युत

कार्यक्रम संख्या 35 पर्याप्त से कम मूल्य (एलटीएआर) पर प्रदत्त जल

निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जिन्हें जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अस्तित्व में और उनका लाभ उठाते हुए पाया जाए।

ड. परामर्श

11. दिनांक 10 जुलाई, 2020 को सलाह परामर्श हुआ और उसमें चीन जन. गण सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। चीन जन. गण सरकार ने कतिपय कार्यक्रमों के अस्तित्व/प्रयोज्यता से इंकार करते हुए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक द्वारा कुछ कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने के बारे में बताया है। तदनुसार, कार्यक्रम सं. 1, 2, 3 4, 6, 8 और 21 को जांच के दायरे से बाहर किया गया है। प्राधिकारी मानते हैं कि अन्य कथित कार्यक्रमों की मौजूदगी, उनकी प्रतिसंतुलनीयता और उनमें प्राप्त लाभ की मात्रा का विश्लेषण करना संगत नियमावली के अनुसार एक जांच के माध्यम से अपेक्षित है।

च. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के चलते कथित सब्सिडीकरण के कारण हुई क्षति, समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से सब्सिडी प्राप्त आयातों की मात्रा में वृद्धि और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त निर्यातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त निर्यातों के कारण हो रही है जो प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता है।

छ. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित उल्लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सब्सिडीकरण, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित सब्सिडीकरण और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सत्य सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा इस जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में

कार्यक्रमों 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 21 के अंतर्गत सब्सिडियों को छोड़कर कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और प्रसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. संबद्ध देश

14. जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

15. आवेदक ने 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (9 माह) की अवधि का जांच अवधि (जिसे आगे पी ओ आई भी कहा गया है) के रूप में प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच में पी ओ आई के रूप में 1 अप्रैल 2019- 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की अवधि को अपनाया है। क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

ट. प्रक्रिया

16. नियमावली के नियम 7 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

17. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg12-dgtr@gov.in तथा dir14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
18. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ड. समय-सीमा

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg12-dgtr@gov.in तथा dir14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. "गोपनीय " या " अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर " गोपनीय " या " अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

26. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
30. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ग. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. नियमावली के नियम 7 (7) के अनुसार कोई हितवद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

त. असहयोग

32. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

Case No. CVD OI -05/ 2020

Subject: Initiation of anti-subsidy investigation concerning imports of “Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/26/2020-DGTR.—1. Association of Man-Made Fibre Industry of India (AMFII) (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for anti-subsidy investigation concerning imports of “Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. The applicant has alleged that material injury to the domestic industry is being caused due to subsidized imports from the subject country and has requested for imposition of countervailing duty on imports of

subsidized subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is “Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers, excluding (a) ready to use yarn/thread on bobbin for embroidery applications and (b) yarn produced through spool spun technology”. The product is also known as Viscose Filament Yarn or Rayon Filament Yarn, Art Silk Yarn, Cellulose Yarn or Rayon Yarn in market parlance. The yarn may be single or twisted or double twisted or untwisted. It can be produced through three different technology/processes - Pot Spun Yarn (PSY), Continuous Spun Yarn (CSY) and Spool Spun Yarn (SSY). Yarn produced through each process finds different usage in different segment because of different specifications. The scope of the product under consideration in the present application is restricted to the yarn produced through Pot Spun Yarn and Continuous Spun Yarn technology.
4. The product resembles silk, cotton and wool in its feel and texture. It is used in making woven fabrics, home furnishings, knitting and others. It is a popular choice for making fabrics such as georgettes, crepes and chiffons.
5. The product is classified under chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs heading 540120, 540331, 540332 and 540341. The applicant has submitted that the product under consideration has been imported under 54012000, 54033100, 54033200, 54034110, 54034120, 54034130, 54034150, 54034170, 54034190, 54034290 and 54034990. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of this investigation.

B. Like Article

6. The applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

C. Domestic industry

7. The Application has been filed by Association of Man-Made Fibre Industry of India (AMFII) with data provided by the domestic producer M/s. Grasim Industries Limited. It has been claimed that the domestic producer M/s. Grasim Industries Limited has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country.
8. As per evidence available on record, the domestic producer expressly supporting the application accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Authority has considered the Applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules.

D. Basis of Alleged Subsidization

9. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the provinces and districts in which producers/exporters are located, and other Public bodies. The applicant has relied upon the relevant laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public bodies.
10. The following subsidies/programs have been alleged by the domestic industry:

I. Scheme Identified in form of Grants:

Program No 1: The Special fund to support the restructuring of the textiles industry and the efforts of Chinese textile companies to “Go Global”

Program No 2: The clean production technology fund/ development and demonstration of high efficiency spinning and clean production technology of differentiated regenerated cellulose fiber

Program No 3: Funds for supporting technological innovation for the technological small and medium-sized enterprise

Program No 4: Traditional industries upgrade fund – Incentive for science and technology funds

Program No 5: Special fund for the development of foreign trade and economic cooperation/ fund for the development of International Economic Relations and Trade

Program No. 6: Special fund for energy saving technology reform / incentive fund for transformation of energy-saving technology

Program No. 7: Research & Development (R&D) assistance grant

Program No. 8: Grants for High and new technology industries

Program No. 9: Fund for effluent treatment plant

Program No. 10: Various grants provided by provincial Authority of Henan province

Program No 11: Various grants provided by provincial Authority of Jilin

Program No.12: Various grants provided by provincial Authority of Sichuan province

II. Schemes identified as Tax & VAT Incentives

Program No. 13: Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies /Income tax reductions under Article 28 of the Enterprise Income Tax Law/ Preferential income tax for non-resident enterprises (NRE) under Article 4 of Enterprise Tax law

Program No. 14: Exemption or reduction from corporate income tax for the enterprises engaging in environmental protection, energy conservation and water conservation projects that meet the requirements

Program No. 15: Preferential tax policies for the additional calculation and deduction of research and development (R&D) expenses/Preferential income tax benefits for research and development investments

Program No. 16: Preferential tax policies for clean development mechanism

Program No. 17: Preferential tax treatment for import of equipment

Program No. 18: Accelerated depreciation on fixed assets

Program No. 19: Tax refund on exports (export tax rebate)

Program No. 20: Tax preference available to companies that operate at a small profit

Program No. 21: Reduced tax rate for productive FIEs scheduled to operate for a period not less than 10 years

Program No. 22: Exemption of tariff and import VAT for imported technologies and equipment

Program No.23: Preferential VAT on integrated utilization of resources/ VAT refunds for FIEs

III. Schemes identified as Loans and Export Financing

Program No. 24: Preferential lending

Program No. 25: Loan guarantee/credit loan guarantee by GOC/Export credit guarantees

Program No. 26: Preferential export financing from the Export-Import Bank of China

Program No. 27: Export seller's credit

Program No. 28: Export buyer's credit

Program No. 29: Export credit insurance subsidies

IV. Schemes identified as Equity Infusions

Program No. 30: Equity infusions

Program No. 31: Debt for equity swaps

V. Schemes identified as Provisions of Goods & Services for LTAR

Program No. 32: Raw material at less than adequate remuneration (LTAR)

Program No. 33: Land /Land use rights provided for less than adequate remuneration (LTAR)

Program No. 34: Electricity provided for less than adequate remuneration (LTAR)

Program No. 35: Water provided for less than adequate remuneration (LTAR)

The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/exporters of the subject goods, during the course of investigation.

E. Consultation

11. Consultation was held on 10th July, 2020 and was attended by the official of the Government of China PR. The Government of China PR denied existence/ applicability of certain programs and non-availment of some of the program by producers/exporters of the product under consideration. Accordingly, program nos. 1,2,3,4,6,8 and 21 have been taken out from the purview of the investigation. The Authority considers that the existence of other alleged programs, their countervailability and extent of benefit therein are required to be analyzed through an investigation as per the relevant Rules.

F. Injury and Causal Link

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place due to the alleged subsidization, resulting in increased volume of subsidized imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India and price suppression effect on the domestic industry. The performance of the domestic industry has been adversely impacted in respect of production, capacity utilization, sales, profits, return on capital employed and cash flow, as a result of subsidized exports from subject country. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by subsidized exports from the subject country to justify initiation of a countervailing duty investigation.

G. Initiation of Countervailing Duty Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating subsidization of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidization and injury, and in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged subsidies except those under programs 1,2,3,4,6,8 and 21 in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. Subject Country

14. The subject country for the investigation is China PR.

I. Period of Investigation (POI)

15. The Applicant proposed 1st April 2019 to 31st December 2019 (9 months) as the period of investigation (hereinafter also referred to as "POI"). However, the Authority has adopted the period 1st April 2019 – 31st March 2020 (12 months) as the POI in the investigation. The injury investigation period will cover the period 2016-17, 2017-18, 2018-19 and POI.

J. Procedure

16. Principles as given in Rule 7 of the Rules shall be followed for the present investigation.

K. Submission of Information

17. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in.
18. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

L. Time Limit

21. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 7(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the

information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

22. All interested parties are advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

23. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
25. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

31. In terms of Rule 7(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

O. Non-cooperation

32. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority